दिनांक 30.01.2016 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप–सह–सदस्य सचिव, राज्य कार्यान्वयन समिति, भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा हेतु संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ताओं के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

स्थाना :– ए0एन0 सिन्हा समाजिक अध्ययन संस्थान, पटना **समय** :– 10:00 बजे पूर्वाह्न

उपस्थिति :– यथासंधारित।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा किया गया। इसके उपरांत बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया एवं एजेंडे की जानकारी दी गयी। बैठक में मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा विभिन्न जिलों में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत किए गए डाटा इंट्री कार्य एवं बकाये राशि के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गयी।

सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं विशेष पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप की उपस्थिति में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित एजेन्डे पर विस्तार से चर्चा प्रारंभ की गयी।

मुख्य रूप से मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा विभिन्न जिलों यथा दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, अररिया, मुंगेर, सहरसा, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा, पटना एवं बेगूसराय में किए गए कार्यो के विरूद्ध लंबित भुगतान एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना से पारित आदेशों के आलोक में अबतक संबंधित जिलों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी।

1. समीक्षा के क्रम में मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल के प्रतिनिधि से यह जानकारी प्राप्त की गयी की एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर 2 प्रतिशत ब्याज माँगने का क्या औचित्य है ?

इस पर एजेंसी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा मुख्यतः दो बातों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया,

- एकरारनामा की कंडिका – 4 का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि उक्त कंडिका के अनुसार Immediately भुगतान करने का प्रावधान है।
- एकरारनामा की कंडिका – 2 का उल्लेख किया गया, जिसमें जिला द्वारा 100 एम0पी0 डाटा (लगभग डेढ़ लाख खेसरा) प्रत्येक माह एजेंसी को उपलब्ध कराया जाना है।

पंचशील सॉफ्टवेयर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अगर उक्त कंडिकाओं का अनुपालन हुआ होता, तो न ही ब्याज की बात आती और साथ ही डाटा इंट्री का कार्य समय पूरा भी हो जाता।

इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि ब्याज का जिक्र एकरारनामा में नहीं है और न ही यह वैधानिक प्रतीत होता है। इसके जबाब में एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि एकरारनामा की कंडिका – 4 में Immediately भुगतान करने का प्रावधान है। इसी के आधार पर 2 प्रतिशत ब्याज का जिक्र बिल में किया गया है। इस पर अपर समाहर्त्ताओं द्वारा बताया गया कि Immediate का मतलब यह नहीं है कि एजेंसी द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज बिल में क्लेम किया जाए।

इसी क्रम में निदेशक महोदय द्वारा एकरारनामा की प्रति की मांग की गयी। कंडिका – 4 एवं 2 का अवलोकन अन्य उपस्थित पदाधिकारियों के साथ किया गया तथा समीक्षोपरांत यह बताया गया कि यह आवश्यक नहीं है और संभवन भी नहीं है कि जिला द्वारा हर हालात में 100एम0बी0 डाटा एजेंसी को उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रशासन के पास और भी जरूरी कार्य होते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से 100 एम0बी0 डाटा प्रतिमाह देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है।

भुगतान के संबंध में यह बताया गया कि एकरारनामा में Immediately का कोई परिभाषा नहीं है। इस पर सम्यक विमर्श करते हुए निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा लगाया जाने वाला 2 प्रतिशत ब्याज का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा और न ही 2 प्रतिशत ब्याज का कोई औचित्य है।

उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं द्वारा इस बिन्दु पर सहमति व्यक्त की गयी। इस पर एजेंसी को यदि कोई आपत्ति हो, तो वे सक्षम स्तर पर अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है। यह भी बताया गया कि Second Print Out में अगर 2 प्रतिशत से ज्यादा त्रुटि मिलती है, तो उस मौजे के बिल से 10 प्रतिशत की राशि एजेंसी से आवश्यक रूप से काटी जाए।

2. समीक्षा के क्रम में अधिकतर जिलों के अपर समाहर्त्ताओं द्वारा यह बताया गया कि इनके जिलों में एन0आई0सी0 द्वारा के0बी0 गणना के अनुसार एजेंसी को पूरा भुगतान कर दिया गया है, फिर भी पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा कैसे बकाया बताया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा एजेंसी के प्रतिनिधि को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

इसके आलोक में पंचशील सॉफ्टवेयर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत डाटा इंट्री का कार्य दो प्लेटफार्म यूनिक्स एवं विण्डोज पर किया गया है। यूनिक्स प्लेटफार्म पर एजेंसी को डेटा के स्ट्रक्चर के आधार पर भुगतान होता था। जहाँ–जहाँ यूनिक्स प्लेटफार्म पर कार्य हुआ है, वहाँ के0बी0 गणना की कोई समस्या नहीं है।

सरकार के पत्र के आलोक में वर्ष 2007 के बाद एजेंसी द्वारा विण्डोज प्लेटफार्म पर डाटा इंट्री का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके लगभग एक वर्ष बाद एन0आई0सी0 द्वारा के0बी0 गणना से संबंधित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया, जो एजेंसी के बिल को 48 प्रतिशत कम कर देता था। एजेंसी द्वारा शिकायत करने पर एन0आई0सी0 द्वारा संशोधित कर पुनः उपलब्ध कराया गया, जो अब भी डेटा के स्ट्रक्चर के आधार के बिल से 16 प्रतिशत कम है। अर्थात 84 प्रतिशत बिल का भुगतान योग्य बताया गया।

चूकि वर्ष 2007 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अब के0बी0 गणना के बदले प्रति खेसरा भुगतान किया जायेगा। एकरारनामा में यह उल्लेख है कि सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि की जाती है, तो एजेंसी का भी रेट बढ़ जाएगा। इसी कारण से एजेंसी के बिल एवं जिला द्वारा भुगतान की राशि में अंतर है।

इसके संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा यह कहा गया कि अभी एन0आई0सी0 द्वारा की गयी के0बी0 गणना के आधार पर जो एजेंसी का भुगतान बनता है, उसी पर चर्चा की जाए। इसके उपरांत निदेशक महोदय द्वारा एजेंसी द्वारा इस योजनान्तर्गत किए गए कार्यो एवं लंबित भुगतान संबंधित जिलावार चर्चा की गयी, जो **परिशिष्ट – 1** पर संलग्न है।

3. समीक्षा के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा यह बताया गया कि राज्य में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत डाटा इंट्री के कार्य में पंचशील सॉफ्टवेयर का काफी योगदान रहा है। परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि डाटा की शुद्धता कितनी है। इसी क्रम में मधुबनी जिला के डाटा में त्रुटि की बात बतायी गयी। एजेंसी द्वारा बताया गया कि एन0आई0सी0 द्वारा गलत Data Conversion के कारण डाटा में गड़बड़ी पायी गयी थी, जिसे अब एन0आई0सी0 द्वारा ठीक कर लिया गया है। निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि अब तक शुद्ध डाटा निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसे शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

4. इसी क्रम में रोहतास जिला के अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा उपलब्ध द्वितीय चेकलिस्ट में छः प्रतिशत से अधिक त्रुटि पायी गयी है। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा यह जानकारी ली गयी कि आपके जिला में अब तक कितने मौजों का सत्यापन कराया गया है। इस पर अपर समाहर्त्ता द्वारा एक मौजा का जिक्र किया गया। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निदेश दिया गया कि यदि किसी मौजे में दो प्रतिशत से ज्यादा त्रुटि पायी जाती है, तो उस मौजा का दस प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि का भुगतान कर दिया जाए।

5. किशनगंज जिला में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत दो एजेंसी कार्यरत है। इस संबंध में बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत डाटा इंट्री का कार्य पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा कराया गया तथा डाटा अद्यतन का कार्य किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। निदेशक महोदय द्वारा यह पृच्छा की गयी कि डाटा अपडेशन कार्य किसी एजेंसी से कराने का आदेश कहाँ से प्राप्त है। विमर्शोपरांत सभी जिलों को निदेश दिया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत डाटा अद्यतनीकरण का कार्य किसी एजेंसी से न कराकर बेलट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध डाटा इंट्री ऑपरेटरों से कराया जाए।

अनुपालन :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप।

6. **<u>भू–अभिलेखों का स्कैनिंग</u>** :–

राज्य के सभी जिलों में जमाबंदी पंजी – ।। एवं सर्वे खतियान इत्यादि का स्कैनिंग एवं अतिरिक्त प्रति निर्माण का कार्य जिलों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि यदि अधिकार अभिलेखों को स्कैनिंग कर सीधे तौर पर संधारित किया जाता है, तो भविष्य में अभिलेखों को खोजने के क्रम में यह कठिनाई उत्पन्न होगी। इस संबंध में बताया गया कि यदि स्कैनिंग/डिजिटल डाटा के संधारण में Quarry System का उपयोग किया जाता है, तो अधिकार अभिलेखों को सर्च करना आसान हो जाएगा और यह एजेंसी की जिम्मेवारी भी बनती है। इस पर निर्णय लिया गया कि स्कैनिंग/डिजिटल डाटा के संधारण में Query System का उपयोग किया जाए एवं वर्त्तमान में मात्र 2 प्रतियों में ही प्रिन्ट आउट किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर सी0डी0 से सर्च किया जाय अथवा संबंधित दस्तावेज की प्रति प्रिन्ट आउट की जाए।

7. **<u>ऑनलाईन म्यूटेशन</u>** :–

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य ऑनलाईन दाखिल खारीज कराना है। सरकार की मंशा के अनुरूप ऑनलाईन दाखिल–खारीज प्रारंभ करने हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। एन0आई0सी0, पटना के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मचारियों दी गयी एवं गुण–दोष के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

8. **<u>बैठक में लिए गए निर्णय</u>** :–

1. किसी भी परिस्थिति में एजेंसी द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज का दावा मान्य नहीं होगा।

2. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए बिल का भुगतान एन0आई0सी0 द्वारा किए गए के0बी0 गणना एवं एकरारनामा के आलोक में आवश्यक रूप से किया जाए।

3. एजेंसी निश्चित रूप से सभी जिलों को अपने कार्य का Detail Status Report उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि बिल हमेशा स्पष्ट रूप से समर्पित किया जाए।

5. एजेंसी को यह भी निदेश दिया गया कि यदि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित कोई समस्या हो, तो अपर समाहर्त्ता से मिलकर प्रतिवेदन दें।

6. डाटा इंट्री के उपरांत डाटा अपडेशन का कार्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं कराया जायेगा। डाटा अपडेशन का कार्य बेलट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा इंट्री आपरेटरों से कराया जायेगा।

7. भविष्य में इस योजना के अंतर्गत होने वाले जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से भाग लेने हेतु सूचित किया जाए।

16/02/16

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
–सह–
सदस्य सचिव,
राज्य कार्यान्वयन समिति

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(पंचशील सॉफ्टवेयर)–315/2015 291 **पटना, दिनांक** :– 18·2·16

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष जिला कार्यान्वयन समिति/सभी अपर समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, जिला कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/16

निदेशक

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(पंचशील सॉफ्टवेयर)–315/2015 291 **पटना, दिनांक** :– 18·2·16

प्रतिलिपि :– मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/16

निदेशक

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(पंचशील सॉफ्टवेयर)–315/2015 291 **पटना, दिनांक** :– 18·2·16

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

16/02/16

निदेशक

परिशिष्ट - 1

PANCHSHEEL SOFTWARES, BHOPAL

(Computerisation of Land Records)

Statement showing pending dues (principal amount) after payment of 84% KB basis (Rohtas only 48%)against district Collectors in Bihar

With reference to the Director's meeting as on 30.01.2016

Name of District	Date of Agreement	Work to complete in	No. Of Mauza Completed	Completed in	Pending dues under Windows after 84% KB basis (Rs.)	pending dues under Unix KB basis	Portion of our demand of dues per Khesra basis	84% KB under Windows basis payments received	Total billed amount
Darbhanga	20.03.2002	12 months	1276	9 years	-	264210	-	4899912	5164122
Bhagalpur	23.09.2002	12 months	1562	24 mouza pending	-	258383.75	-	2289833.25	2548217
Madhubani	08.01.2003	12 months	1115	9 years	-	1245487.65	-	5281685.35	6527173
Araria	31.05.2007	12 months	758	7 years	-	158446.79	-	2557661.21	2716108
Munger	10.12.2007	12 months	155	only 152 mouza	-	31110	-	69218	100328
Saharsa	01.11.2007	10 months	142	330 mouza pending	82253	-	54584	246807	383644
Bhojpur	14.11.2007	12 months	1241	45 mouza yet	559098	-	1676656	3617684	5853438
Vaishali	11.12.2007	12 months	1582	8 years	779642	-	2808762	3581129	7169533
Muzaffarpur	14.02.2008	8 months	994	4 years	734724	-	2969860	3956856	7661440
Rohtas	30.09.2008	10 months	2033	158 mouza pending	2157624.4	-	297410	1540962.6	3995997
Sitamarhi	02.11.2010	10 months	737	105 mouza pending	839985	-	856238	4885393	6581616
Sheohar	24.01.2011	6 months	309	completed	171013	-	131988	897820	1200821
Madhepura	29.10.2011	10 months	112	completed	83689	-	888284	409113	1381086
Patna	24.05.2012	12 months	1151	82 mouza pending	1640316	-	570712	4170292	6381320
Begusarai (to display later)	24.09.2012	6 months	855	only 855 mouza	-	-	-	-	-
				Total	7048344.4	1957638.19	10254494	38404366.41	57664843

Note: 1. District Rohtas has paid only 48% as against 84% paid by other collectors

2. Our demand per khesra basis is for working under Windows and with reference to PS Order letter No 1928 dated 07.12.2012